सम्पादक के नाम

लड़की कहाँ जाए अब

हरियाणा के सिरसा जिला के गाँव फग्गू में एक नाबालिग भाई ने अपनी बड़ी बहन को धारदार हथियार से काट डाला! लड़की बुरी तरह जख्मी है और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है! हमला इतना घातक था की लड़की की बाजू लटक गयी, ऊँगली कट गयी और कान नाक चेहरे और टांग पर गहरे जख्म हैं!

गाँव चुप्प है, लड़की सहमी हुई है! अग्नि परीक्षाओ का काल गया नहीं है और उदारीकरण की 21वी सदी में भी हम अनुदार इतने हैं की लामबद्ध हो लड़के को बचाने के तमाम उचित-अनुचित तरीके अपनाते हुए लड़की के विरोध में आ कर खड़े हो गए हैं! पुरुष सत्ता का खौफ इतना गहरा है कि कुछ मौजिज लोगो ने लड़के के कृत्य को सही ठहराते हुए लड़की पर तमाम आरोप रोपित कर दिए और लड़के को बचाने की एक तरफ़ा घोषणा कर दी है ! पुलिस की डायरी में अभी यह केस पक्का नहीं हुआ है, घटना 24 सितम्बर की है, पुलिस को कारवाही ना करने के संकेत जारी किये गए हैं! लड़की से बयान दिलवाया जा रहा है कि उसका हाथ चारा काटने वाली मशीन में आ गया था जिसकी वजह से दुर्घटना हुई!

जिला के हम तमाम बुद्धिजीवी चुप हैं, अखबार ने एक दिन हादसा चिन्हित किया उसके बाद वह भी चुप है, पुलिस भी चुप है, समाज भी चुप है! चुप्पियों के दौर में लड़की कैसे बोल लेगी, महत्ती सवाल सिर्फ एक है! पूरे गाँव की लड़कियों, महिलाओ को इस घटना के बाद कड़ा सांकेतिक सदेश दे दिया गया है कि उदारीकरण अर्थशास्त्र का ही विषय है, विचारो के संदर्भ में इससे दूर रहें , हम गाँव हैं, बंद ही रहेंगे हर परिवर्तन से!

मामला यह है की लड़की का पिता नहीं है लड़की अपने करियर को लेकर संजीदा है और नर्सिंग के कोर्स के साथ-साथ पार्ट टाइम रोजगार भी कर रही है, किसी पंजाबी गाने में उसे एक्टिंग का मौका मिला और उसने उस गाने में मुख्य किरदार निभाया, भाई को यह गंवारा नहीं हुआ और भाई ने बर्बरता पूर्वक हमला कर डाला!

एक लड़का जो अभी बालिग़ हुआ नहीं है,बालिग़ होने की कगार पर है, उसे आखिर किसने बताया कि लड़की का गाने में एक्टिंग करना चरित्र हीनता का मामला है! गाँव अगर इस गाने को केंद्र वजह मानकर यह घोषणा कर रहा है कि लड़की ठीक नहीं थी तो यह अधिकार गाँव के पास कहाँ से आ जाता है! समाज को भी यह अधिकार किसने दिए कि वह किसी को चरित्र का प्रमाण पत्र दे! पंचायती लोगो का जघन्यता के पक्ष में खड़ा हो जाना समाज की संवेदनहीनता का घिनौना सच है! हम ऐतिहासिक सत्य जानते हैं कि आप वही लोग हैं जो सीता माता के निष्काषन पर भी तर्क खोज लेते हैं! आप वही लोग हैं जिन्होंने हजारो सालो में कोई न कोई तर्क गढ़कर मार-मार डाली बेटियां, काट-काट डाली स्त्रियां!

आप कहिए कि उदारीकरण के बाद मुल्क उदार हुआ है, आप कहिये कि यह 21वी सदी का भारत है, आप कहिये कि आधुनिक हो रहा है हमारा मुल्क और हम भी आधुनिक हो रहे हैं साथ ही साथ। सरकार जब कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तब उदार होने, आधुनिक होने और 21वी सदी में आ पहुंचने के हमारे तमाम दावे खुद सरकारी स्तर पर ही संदिग्ध हो जाते हैं। और सोच के आधुनिक होंने के तमाम दावों के विपरीत जब हम सोच के 100 साल पीछे होने का नँगा सच नँगे रूप में सामने देखते हैं तो हमारे शब्द हमारे गले मे ही घुट कर मर जाते हैं।

गाँव ठीक ठाक साक्षर है, आधे फन्नेखाह लोग अलग अलग नशा करते हैं, तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सालों से वहां सरकारी स्कूल होने की वजह से अक्षर ज्ञान अधिकतर लोगो को है! क्या अक्षर ज्ञान ही हमारे उन्नत होने का सूचकांक है? सोचिये तो जरा ! क्या नशा किसी तरह की चरित्रहीनता में नहीं आता? सोचिये तो जरा! क्या गाँव के तथाकथित पुरुष ठेकेदारों ने अपने अपने जीवन में चरित्र की शुचिता के तमाम नियम निभाए? क्या लड़की की जगह लड़के पर हमला हुआ होता तब भी गाँव हमलावर लड़के की एक तरफ़ा पैरवी करता? सोचिये तो जरा

लड़की कहती है मुझे रहना तो भाई के पास ही है, अपाहिज भी हो गयी हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ अब ! लड़के के पक्ष मे खड़े समाज के ठेकेदारों, बताओ लड़की के लिए रास्ता क्या है?

- वीरेंदर भाटिया

सर्जिकल स्ट्राइक दिवस : विचार या विचार की दरिद्रता!

1. ये स्ट्राइक 2016 में हुई थी। फिर पिछले साल यानी 2017 में क्यों भुला दिया? ये 2018 है और 2019 में चुनाव होना है! क्या माजरा है? सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी हुई पर किसी ने 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' मनाने को तो नहीं कहा!

2. Surgical strike पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए की गई कि वह आतंकियों को शह नहीं दे और सरहद पर खुराफात न करे! क्या सरहद पर सब ठीक हो गया?

3. अधिकृत आंकड़े बताते हैं कि सरहद पर और कश्मीर में हमारे जवानों की मौतों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है। सन् 2016 का आंकड़ा बीते छह सालों में सबसे अधिक बताया गया।

4. देश के अनेक इलाकों, खासकर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र आदि में अपने नागरिकों पर ही जो शासकीय एजेंसियों की 'सर्जिकल स्ट्राइक'(पुलिसिया 'फेक एनकाउंटर' और सत्ता संरक्षित गुंडा गिरोहों द्वारा 'माब लिंचिंग')होती रहती है, उसका क्या होगा?

5. आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने बाहर जाकर कारवाई की (हम इन्हें जायज या नाजायज नहीं कह रहे हैं)। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा आपरेशन था- अमेरिका का पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के सफाए का आपरेशन। क्या अमेरिका में कभी 'ओसामा विरोधी सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' मनाने की बात कभी किसी ने सुनी या किसी के दिमाग में ऐसा विचार आया?

6.दुनिया में ज्यादातर देशों के उनके पड़ोसियों के साथ के विवाद अंततः वार्ता से ही हल हुए, युद्ध से नहीं। ऐसे में अगर कभी भारत-पाकिस्तान के बीच वार्ता, समझौता या शांति के प्रयास शुरू हुए तो 'सर्जिकल सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' का क्या होगा? उसकी क्या प्रासंगिकता होगी तब?

7. सरकार विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में भी 'पराक्रम' के इस दिवस को जबरन मनवा रही है! वाइस चांसलर और अन्य अधिकारी दुम हिलाते हुए हुक्म तामील कर रहे हैं! पर ठीक इसी दौरान दुनिया के स्तरीय विश्वविद्यालयों का एक सूचकांक हाल ही में जारी हुआ। दुनिया के श्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों की सूची में इस बार भारत के एक भी विश्वविद्यालय को जगह नहीं मिली!

हे भारत के वीर-बांकुड़ों, आप इत्ती छोटी सी बात क्यों नहीं समझते कि विश्वविद्यालय ''पढ़ाई'' के लिए होते हैं, 'पराक्रम-प्रदर्शन' के लिए नहीं!

8. पराक्रम ही दिखाना है तो शिक्षा, सेहत , कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, खेलकूद, नरेंद्र वैज्ञानिक आविष्कार और खुशहाल मुल्क बनाने में दिखाओ!

9. इन सभी क्षेत्रों में जिस दिन भारत आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान या दक्षिण एशिया का कोई भी मुल्क भारत के आगे नतमस्तक होगा! सरहद के विवाद भी सुलझते नजर आएंगे! अगर आप सचमुच देशप्रेमी हैं तो ईमानदारी से सोचिए।

- उर्मिलेश उर्मी

खबर (दार) झरोखा — रवीश कुमार

दिल्ली के रेस्त्रां में काम करने वालों ने मिलकर चिट्ठी भेजी है

सेवा में,

श्रीमान NDTV प्रमुख महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं, और मेरे साथ मेरे बहुत सारे मित्र भी कार्यरत हैं। महोदय, दिल्ली के रेस्टोरेंट में काम करने वाले वर्करों का बहुत ही बुरा हाल है। हमें महीने की दो ही छुट्टी मिलती है, ड्यूटी 10 से 12 घंटे की होती है। स्टाफ खाना सड़ी हुई सब्जियों का मिलता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, रक्षा बन्धन सारे त्योहार हमने आज तक अपने परिवार के साथ नहीं मनाए हैं।

सैलरी हमें 8 हज़ार से 9 हज़ार मिलती है और आजकल हमारे रेस्टोरेन्ट मालिक कह रहे हैं कि अपना आई डी प्रूफ दो फिर हमारे आई डी प्रूफ को स्कैन करके गूगल पर पता नहीं कौन सा फार्म भर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे मोबाइल में जो ओ टी पी आया है, बताओ।

महोदय, दिल्ली में जितने भी रेस्टोरेन्ट है, अधिकतर दो नंबर में चल रहे हैं। क्योंकि एम सी डी वाले हर महीने का पैसा लेते हैं। फूड सैंपल वाले सैंपल पास कराने का 20,000 ले जाते हैं। लेबर इंस्पेक्टर 3000 रुपये महीना ले जाता है। रेस्टोरेन्ट मालिक से ज़्यादतर रेस्टोरेन्ट के पास लाइसेंस नहीं है। और तो और रेस्टोरेन्ट में जो खाना बनाते हैं उनके लिए हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं होता है।

रेस्टोरेन्ट बाहर से जितना सुन्दर होता है, अन्दर उतना ही गंदगी होती है। दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। PF, ESI कागज़ों में कटता है पर स्टाफ को नहीं मिलता है। कई रेस्टोरेन्ट हैं जो पैसा तो बहुत कमाते हैं स्टाफ को हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं देते हैं। किचन स्टाफ कई बार गन्दे हाथों से ही खाना बनाने को मजबूर हैं। सरजी हमारी उम्मीद है, NDTV हमारी आवाज़ बनेगा। बाकी न्यूज़ चैनल तो बिकाऊ हैं, पैसे लेकर न्यूज़ दिखाते हैं।

आपका।

(मुझे रोज़ कई पत्र आते हैं। हर चिट्ठी एक नई दुनिया लेकर आ जाती है। कई बार यहां पोस्ट कर देता हूं शब्दश टाइप कर। सारी स्टोरी कहां कर सकता हूं। पता नहीं कब सब ठीक होगा। शायद कभी नहीं। आपके लिए इसलिए लिखा कि बस जान जाएं। अन्तर्देशीय पत्र कार्ड से चिट्ठी आई है।)

गौतम नवलखा / एक 'शहरी नक्सल' का बयान

मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुमत और असहमति वाले न्यायाधीशों का उनके फैसले के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने हमें इस मामले में राहत हासिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया, साथ ही मैं भारत के जनपक्षधर नागरिकों और वकीलों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारी ओर से ज़ोरदार लड़ाई लड़ी, जिसकी स्मृतियां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हमारे समर्थन में कायम उस एकजुटता के आगे मैं नत हूं, जिसने सरहदें लांघ लीं।

मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी आज़ादी वापस मिली है। मैं ऐसा आह्लादित हूं कि इसका कोई छोर नहीं।

मेरे प्रिय दोस्तों और वकीलों ने नित्या रामाकृष्णन, वारिशा फरासत, अश्वत्थ और कानूनी व लॉजिस्टिक्स टीम के नेतृत्व में मुझे आज़ादी दिलाने के लिए वास्तव में ज़मीन और आसमान को एक कर डाला। पता नहीं मैं उनका कर्ज कभी चुका पाऊंगा या नहीं। और उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी, जिन्होंने सर्वोच्च अदालत में हमारी पैरवी की है। कुछ बंदिशों के बावजूद नज़रबंदी की इस अवधि का मैंने अच्छा उपयोग किया, इसलिए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है।

मैं हालांकि अपने सह-आरोपियों और भारत के दसियों हज़ारों दूसरे राजनीतिक बंदियों को नहीं भुला सकता जो अपनी वैचारिक आस्?थाओं या अपने खिलाफ लगे गलत आरोपों अथवा यूएपीए कानून के तहत कैद हैं। इसी मामले में मेरे सह-आरोपी जेल के भीतर हो रहे गलत बरताव के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और उन्होंने खुद को राजनीतिक बंदी का दरजा दिए जाने की मांग उठायी थी। दूसरे राजनीतिक बंदियों ने भी समय-समय पर भूख हड़ताल कर के लगातार यही मांग उठायी है। नागरिक स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार आंदोलन के लिहाज से उनकी आज़ादी और उनके अधिकार अमूल्य हैं।

आज हालांकि जश्न मनाने के वाजिब कारण हैं। मैं एलजीबीटीक्यू समुदाय के साथियों को हाल ही में उनकी शानदार जीत के लिए सलाम करता हूं जिन्होंने अथक संघर्ष किया है, जिसके चलते एक ऐसे सामाजिक सुधार आंदोलन के द्वार खुल गए हैं जैसा कि बाबासाहब आंबेडकर ने जाति के उन्मूलन के लिए खड़ा किया था और हमसे ''शिक्षित, संगठित व आंदोलित'' होने का आह्वान किया था। हमारी एकजुटता में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आपकी दृढता ने हमें बदलने को विवश कर डाला। आपने हमारे चेहरे पर मुस्कान लौटा दी और हमारी जिंदगी में सतरंगी रंग भर दिए।

इसके साथ ही भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण और उनके साथियों सोनू व शिवकुमार को कैद से मिली आज़ादी विशेष रूप से आश्वस्तकारी है क्योंकि यह समाज में निहित जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ ज़मीन से उठे ज़बरदस्त प्रतिरोध की ताकत को दर्शाती है।

एकजुट लेफ्ट पैनल की ऐतिहासिक जीत के लिए जेएनयू छात्र संघ के दोस्तों को मेरा सलाम, जो एक बार फिर से साबित करता है कि एकजुट होकर प्रतिरोध करना वक्ती ज़रूरत है- केवल तभी हम अत्याचार का सामना कर सकेंगे और ऐसा संघर्ष खड़ा कर सकेंगे जिसके लिए जनता का समर्थन जुटाया जा सके।

दोस्तो, सच्चाई और ईमानदारी से लदे शब्द गोली और गाली से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, आज यह साबित हो रहा है। हमारे गीत और कविताओं में जोश है और हमारे काम और लेखनी का आधार तर्क व तथ्य हैं।

मेरे सभी करीबी और प्रिय दोस्तो, आइए मिलकर हम अपनी संवैधानिक स्वतंत्रताओं के हक में और उत्पीड़न व शोषण के सभी रूपों के खिलाफ़ आवाज़ उठाना जारी रखें।

इस मौके पर पाश के ये अनमोल बोल दोहराए जाने चाहिए:

''हम लड़ेंगे साथी
कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता
हम लड़ेंगे
कि अभी तक लड़े क्यों नहीं
हम लड़ेंगे
अपनी सज़ा कबूलने के लिए
लड़ते हुए मर जाने वालों की
याद जिंदा रखने के लिए
हम लड़ेंगे साथी''

लाल सलाम
गौतम

बीमा व्यवसाय में राज्यपाल बना अंबानी एजेंट

सुरेंद्र ग्रोवर

नरेंद्र मोदी पर कैसा क़र्ज़ है अनिल अम्बानी का, जिसे चुकाने के लिए जनता की जेब काट अम्बानी की तिजोरी भर रहे हैं. ?

केंद्र सरकार ने रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक नई कारिस्तानी की है.. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए रिलायंस की हेल्थ बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य कर दिया है..

20 सितम्बर को जारी इस आदेश में राज्यपाल ने कहा है कि सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बजाय रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बीमा लिया जाए..

राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि सरकार ने रिलायंस के साथ समझौता किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को सालाना 8,777 रुपए और पेंशनधारियों को 22,229 रुपए की किस्त जमा करनी होगी..

यह बीमा करवाना राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों (गैजेटेड और नॉन गैजेटेड) राज्य के विश्वविद्यालयों, आयोगों और तमाम स्वायत संस्थानों के लिए जरूरी होगा..